

168-Polky
08/10/2020

999/ACTT/POLICY
07-10-2020

C-998067/CGST
07/10/2020

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1st FLOOR, NEW DELHI-110 002

No. F.3 (45)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 103

Dated: 30/8/20

ORDER No. 61/2020- State Tax

No. F.3 (45)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ —WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the said Act) provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clauses (a) to (e) as under: -

- (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
- (b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
- (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (1) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or
- (e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts; -

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the said Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clauses (c) and (d) of said sub-section are as under: -

- (c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
- (d) by making it available on the common portal; or

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 30 of the said Act provides for application

Ms. Parvati Incharge, JTC

A
12/10/2020

13.10.20
S. Manu

Mr. 8/10

ACCP

Yam
11/10/20

Def (a)
Naghi
5/10

791/98
15/10/2020

for revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order;

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the said Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the said Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month;

AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the said Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the said Act and the period of thirty days provided for application for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the said Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the said Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the said Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration; the said Act being a new Act, these taxpayers could not apply for revocation of cancellation within the specified time period of thirty days from the date of service of the cancellation order, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the said Act;


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. **Short title.**—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2020.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating the period of thirty days for filing application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act for those registered persons who were served notice under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and where cancellation order was passed up to 12th June, 2020, the later of the following dates shall be considered:-

- a) Date of service of the said cancellation order; or
- b) 31st day of August, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 30/8/20

No.F3(45)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 103

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनाधी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, गार्ड दिल्ली-110002

सं.पा. 3(45)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/103

दिनांक: 30/8/20

आदेश संख्या 01/2020-सपच कर

सं.पा. 3(45)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/ : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'डीजीएसटी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ड) में वर्णित परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार से है, जहाँ :-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विधियों के अधीन ऐसे चैपबर्कों का उल्लंघन किया है जो निर्दिष्ट किए जाएं; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर का संवाध करने वाले व्यक्ति ने, तीन ज़मदारी कर अपघियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति से बिना किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन संवेद्यता रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्ति किया गया है;

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर विधे बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 189 की उप-धारा (1) नोटिस की तारीख (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है, उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समाप्त या समय-समय पर संशोधित उत्तरे ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तारीख की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनियमक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनियम या आदेश से व्यक्त किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को 'उक्त विनियम या आदेश' संशुचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील काइल करने का उपबंध करती है और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सहायक करती है कि, यदि उसका यह समझा हो जाता है कि, अपीलकर्ता तीन मास की पूर्णता अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, यह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तारीख के द्वारा डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील काइल करने की अवधि और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के ब्यापक अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण करने में असमर्थ हैं। जो एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन काइल के विनिर्दिष्ट समय अवधि, जो रद्दकरण आदेश की तारीख की तारीख से तीस दिन के भीतर है, में नहीं कर पाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2020 है।

2. कठिनाइयों को दूर करने हेतु, यह इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन काइल करने के लिए तीस दिन की अवधि की मरमा हेतु, ये रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नोटिस तारीख हुई थी और 12.06.2020 तक रद्दकरण आदेश पारित हुआ है, के लिए निम्नलिखित तिथियाँ में से उदाहरणों तिथि को माना जाएगा:-

क) उक्त आदेश के संघार की तारीख, या

ख) अगस्त का 31 वाँ दिन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)
उप सचिव- IV (वित्त)

संख्या 03(45)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएन-IV/103 दिनांक: 30/8/20
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - धार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्यधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. आई. फाइल।
11. डेब सर्किल।

(मनोज कुमार)
उप सचिव- IV (वित्त)